

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 308/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/509

प्रार्थनी	बनाम	विप्रार्थीगण
तगूदेवी पुत्री चुनाराम पत्नि सीताराम		1.दूदाराम पुत्र चूनाराम
जाति मेघवाल निवासी आसोतरा हाल		2.गवरीदेवी पत्नि चूनाराम
मेघवालो का बास,बालोतरा तहसील		3.अचलाराम पुत्र डायाराम
पचपदरा व जिला बालोतरा		4.अर्जुनराम पुत्र डायाराम
		5.डूंगरराम पुत्र डायाराम
		6.अमराराम पुत्र घूंगाराम
		7.आबाराम पुत्र घूंकाराम
		8.दलाराम पुत्र घूंकाराम
		9.भगाराम पुत्र घूंकाराम
		10.सोमादेवी पत्नि घूंकाराम
		11.कमलेश पुत्र देदाराम
		12.गंगाराम पुत्र देदाराम
		13.जितेन्द्र पुत्र देदाराम
		14.रामाराम पुत्र देदाराम
		15.हिन्दूराम पुत्र देदाराम
		16.डामरराम पुत्र देदाराम
		17.ददादेवी पत्नि देदाराम
		18.गीगा पुत्र नवाराम
		19.गोकलराम पुत्र वनाराम जाति मेघवाल
		निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
		20.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथिति-

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थनी
2. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता विप्रार्थी 1 से 18
3. विप्रार्थी संख्या 19 व 20 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक- 25.6.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थनी की ओर से मूलवाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है, जिसमें उल्लेखित किया कि मुतवफी चैनाराम व उसके भाईयो की सहखातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा की खसरा संख्या 775,778,847,851 कुल रकबा 21.18 बीघा व खसरा संख्या 1470,6479,2346/1470 कुल रकबा 94.17 बीघा भूमि अवस्थित थी, जिसमें 1/2 हिस्सा नैनाराम के परिवार का व 1/2 हिस्सा कोलाराम के परिवार का था। प्रार्थनी व विप्रार्थी संख्या 01 भाई-बहन है व विप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थनी की माता है। इस प्रकार प्रार्थनी चूनाराम की विधिक वारिसान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि में प्रार्थनी के जन्म से ही खातेदारी हक पैदा हो गए थे। प्रार्थनी के पिता चूनाराम के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ प्रार्थनी का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रार्थनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए विवादित भूमि में प्रार्थनी का नाम दायर नहीं किया गया, जबकि प्रार्थनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थनी का नाम नहीं होने के कारण विप्रार्थी प्रार्थनी को मौके से बेदखल करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थनी द्वारा मूलवाद के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरीए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता द्वारा मूलवाद में प्रतिवादी/विप्रार्थी संख्या 1 से 18 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा आवेदन-पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा विप्रार्थी संख्या 19 व 20 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थनी ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थनी को सफल होने की पूरी संभावना है, कि मुतवफी चैनाराम व उसके भाईयो की सहखातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा की



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 775,778,847,851 कुल रकबा 21.18 बीघा व खसरा संख्या 1470,6479,2346/1470 कुल रकबा 94.17 बीघा भूमि अवस्थित थी,जिसमें 1/2 हिस्सा नैनाराम के परिवार का व 1/2 हिस्सा कोलाराम के परिवार का था। बाद में भाई बंटवाड़े में प्रार्थिनी के पिता चूनाराम की खातेदारी भूमि के नए खसरा न कायम हुए,जो आवेदन पत्र में वर्णित किए गए हैं। प्रार्थिनी व विप्रार्थी संख्या 01 भाई-बहन हैं व विप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थिनी की माता हैं। इस प्रकार प्रार्थिनी चूनाराम की विधिक वारिसान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि में प्रार्थिनी के जन्म से ही खातेदारी हक पैदा हो गए थे। प्रार्थिनी के पिता चूनाराम के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ प्रार्थिनी का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन प्रार्थिनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए विवादित भूमि में प्रार्थिनी का नाम दायर नहीं किया गया,जबकि प्रार्थिनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थिनी का नाम नहीं होने के कारण विप्रार्थी प्रार्थिनी को मौके से बेदखल करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू हैं। इस कारण प्रार्थिनी के पक्ष में स्थगन आदेश को जारी किया जाना आवश्यक है,यदि स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता है,प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थिनी के पक्ष में बनते हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थिनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थिनी ने विप्रार्थी के विरुद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से विपरीत जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद-पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य हैं,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थिनी विप्रार्थी संख्या 01 की न तो बहन हैं और न ही विप्रार्थी संख्या 02 की पुत्री हैं। प्रार्थिनी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। प्रकरण में दर्शाया गया सजरा भी गलत बताया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थिनी का विवादित आराजी में कोई हक हकूक नहीं है और न ही प्रार्थिनी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। चूनाराम के फौत हुए लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है,इतने वर्षों तक प्रार्थिनी द्वारा विवादित आराजी के संबध में कोई चाराजोही नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिनी का विवादित आराजी में कोई हक निहित नहीं है। विवादित आराजी के विप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं और रिकार्डेड होने के उपरांत भी स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिसके कारण विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है,इस कारण प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थिनी के पक्ष में नहीं बनकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गालोतरा

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिपेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 2906/770,3003/847,3446/1470 भूमि पर प्रार्थीनी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक जारी किया जा सकता है अथवा नहीं। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(i) सर्वप्रथम प्रथम द्विष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है, के संबंध में विवेचन किया जा रहा है, जिसमें पाया कि मूलवाद अन्तर्गत धारा 80, 83, 108 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर प्रार्थीनी पक्ष द्वारा मुख्य उजर उठाया कि विवादित भूमि पुरतैनी है, प्रार्थीनी मुतवफी चूनाराम की विधिक वारिसान होने के कारण अपना हक हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने की हकदार है, ऐसी स्थिति में दौराने विचारण चाद विवादित भूमि में रेकर्ड एवं मौका स्थिति में फेरबदल नहीं हो, इस कारण स्थगन आदेश जारी किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थी पक्ष द्वारा मुख्य उजर उठाया गया कि प्रार्थीनी मुतवफी चूनाराम की विधिक वारिसान नहीं है, इस कारण स्थगन आदेश प्राप्त करने की हकदार नहीं होने के कारण आवेदन खारिज किया जावे।

इस प्रकार दोनों पक्षों के अपने अपने उठाए गए उजर-एतराज के आधार पर न्यायालय हाजा के सामने मुख्य विवाद का बिन्दु सामने यह आया है कि क्या विवादित भूमि पुरतैनी है तथा प्रार्थीनी मुतवफी चूनाराम की जायन्दा पुत्री है अथवा नहीं। उक्त बिन्दु का निस्तारण हस्तगत प्रकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य विवाद के बिन्दु का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने पर क्षति होगी। जबकि प्रार्थीनी विवादित भूमि की खातेदार भी नहीं है, तो उन्हे क्षति होनी की संभावना भी नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रथम द्विष्यता मामला प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है।

6(ii). इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है, क्योंकि विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थीनी/वादीनी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, वंटवाड़ा एवं रथाई निषेधाज्ञा बाबत लाया गया है, जो कि निर्णय मूलवाद में तय किया जावेगा। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं मानता है, क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी उसे पक्ष में बनता है, न कि प्रार्थीनी के पक्ष में। इस कारण सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है।



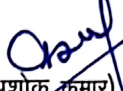
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) तालोतरा

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु प्रार्थिनी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि प्रथम द्वय्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी अपनी पक्ष में साबित करने में असफल रही है। ऐसी सूरत में रथगन आदेश को जारी किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि यदि रथगन आदेश को जारी किया जाता है,तो विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी,न की प्रार्थिनी को। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी रथगन आदेश प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इस कारण अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।


7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्वय्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही प्रार्थिनी के पक्ष में नहीं बनते हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का आवेदन खारिज योग्य है।

:आदेश:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.6.2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

